from the Reserve Bank of India to Public Sector Banks to make prompt payment of pension and Dearness Relief to Central Government Pensioners. The concerned bank branches all over the country, including those in Pauri Garhwal, in Uttar Pradesh are to follow the above instructions. The above instructions have been reiterated on 9th January, 1996, by the Reserve Bank of India to Public Sector Banks, to ensure that pension/family pension and other admissible pensionary benefits are promptly paid to avoid complaints from the pensioners/ Pensioners Associations.

गैस के नकली सिलेंडरों की आपूर्ति

237. श्री नागमणि:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैस के नकली सिलेंडरों की आपूर्ति को रोकने के लिए गत दो वर्षों के दौरान गैस एजेंसियों पर कोई छापे मारे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू): (क) और (ख) सरकारी एल पी जी विपणन कम्पनियां डिस्ट्री ब्यूटरों तथा परिवहनकर्त्ताओं इत्यादि के पास। नकली सिलेन्डरों के परिचालन का पता लगाने के लिए नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण करती है। राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर कुछ एक छापे भी मारे जाते हैं जिससे संबंधित सूचना का रख रखाव नहीं किया जाता है और यह इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

1993-94 तथा 1994-95 के दौरान एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों/परिवहनकर्त्ताओं से जब्त किए गए/पता लगे नकली सिलेन्डरों की संख्या निम्नवत् है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94	1994-95
आंध्र प्रदेश	89	82
बिहार	-	-
गोआ	1	-
गुजरात	135	181
हरियाणा	224	241
हिमाचल प्रदेश	9	-
जम्मू और कश्मीर	14	13
कर्नाटक	10	37
केरल	4	0
मध्य प्रदेश	81	45
महाराष्ट्र	51	40
उड़ीसा	20	6
पंजाब	132	1051
राजस्थान	68	303
तमिल नाडु	24	41
उत्तर प्रदेश	1671	1958
पश्चिम बंगाल	19	9
संघ राज्य क्षेत्र		
दिल्ली	166	237

Setting up of Bio-Gas Plants in Rajasthan

*238. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Rajasthan has the potential for production of 256 crore cubic metres of bio-gas;

(b) if so, the amount of subsidy given to Rajasthan for installation of bio-gas plants particularly in the hilly regions of Udaipur, Dungarpur and Sirohi, during the last three years;

(c) the steps taken by the Centrol Government to increase the generation of power through bio-gas units as on the 1st May, 1996, State-wise; and

(d) whether there is any proposal to set up more bio-gas plants in Rajasthan during 1996-97?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Yes, Sir. In the Perspective Plan of Rajasthan for 2010 A.D. prepared by the State Government, a theoretical potential of production of 256 crore cubic metres of biogas per year has been indicated, based on the assumption that the entire estimated total quantity of about 70 million tonnes of dung produced from 1.72 crore cattle population in the State in processed in Biogas plants.

(b) Under the Central Sector Schemes namely, National Project on Biogas Development and Community, Institutional and Night-Soil based Biogas Plants Programme, a total sum of about Rs. 3.90 crore and Rs. 9.00 lakhs respectively was released to the State Government of Rajasthan towards central subsidy and other incentives during the last three years, i.e. 1993-94 to 1995-96. The State Government has in turn released subsidy amounting to a total of about Rs. 45.37 lakhs to the districts of Udaipur, Dungarpur and Sirohi during the period. Besides, the Khadi and Village Industries Commission and All India Women's Conference are implementing these schemes in some districts of the State, for which funds were released separately.

(c) Steps taken for popularisation of large size biogas plants, which can also be used for generation of motive power, include provision of central subsidy and technical, training and publicity support. As on the 1st May, 1996, the targets allocated for such plants for 1996-97 are as under:-

State	Target for 1996-97
Andhra Pradesh, Assam Himachal Pradesh, Orissa Rajasthan and Sikkim	1 each
Gujarat and Delhi	5 each
Haryana	4
Karnataka	10
Kerala	3
Madhya Pradesh and West Bengal	2 each
Maharashtra	24
Punjab	20
Tamil Nadu	15
Uttar Pradesh	40
Others (Khadi & Village Industries Commission, Sulabh International, etc.	64
Total	200

(b) Against the demand of the State Government of Rajasthan for a target of 1500 family type biogas plants for 1996-97, the State has been advised, in the light of the findings of the recent Evaluation Survey Study of Biogas Plants conducted by the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, to take measures to complete and commission all incomplete and un-commissioned plants, at least of the last three years.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मकानों पर अधिक शास्तिक ब्याज लगाया जाना

'239. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तात्कालिक बिक्री योजना (इंस्टेंट सेल स्कीम) के अन्तर्गत नवनिर्मित मकानों का आवंटन/विक्रय धनराशि के एकमुश्त भुगतान पर अथवा 18 प्रतिशत ब्याज सहित त्रैमासिक किश्तों पर किया जा रहा है;

(ख) क्या किश्त का विलंब से भुगतान करने पर 21 प्रतिशत की दर से शास्तिक ब्याज लगाया जाता है और इस प्रकार कुल ब्याज बहुत भारी अर्थात् 39 प्रतिशत हो जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्राधिकरण द्वारा आवंटितियों को कोई राहत दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वैंकटेस्वरलू): (क) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बताया है कि तात्कालिक बिक्री योजना के तहत प्राधिकरण केवल उन मकानों का निम्नलिखित शर्तों पर, आबंटन कर रहा है, जो या तो बहुत पहले निर्मित हुए और आवास स्कीमों की घोषणा के बाद भी नहीं बिक सके, अथवा जिन के लिए जमा राशि आबंटियों ने आबंटन के बाद वापस ले ली या जो अन्य विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिये गये थे:

(1) एक माह के भीतर एक मुश्त भुगतान किया जाने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा बल्कि मकान लागत में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

(2) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भुगतान छह तिमाही किश्तों में करने की सुविधा है, जिसमें 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज शामिल है।

(3) अन्य वर्गों के लिए 8 तिमाही किस्तों में भुगतान की सुविधा है, जिसमें 18 प्रतिशत की ब्याज दर शामिल है।

(ख) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जी०डी०ए०) नियमों के अनुसार इस योजना के तहत नियत तारीख को